फुल बेंच

माननीय न्यायालय आर एस नरूला, C.J. और प्रेम चंद जैन और एम. आर. शर्मा, जे. जे.

शाम रतन नेवार,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य, -उत्तरदाता

सिविल रिट नं. 1970 का 2876

6 अगस्त, 1974

पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम (1935 का 5)-धारा 3 क्या यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

अभिनिर्धारित किया गया कि केवल इसलिए कि एक निश्चित कानून सरकारी देय राशि की वसूली को प्रभावी बनाने के लिए दो प्रक्रियाओं को विहित करता है, जिनमें से एक अन्य की तुलना में कठोर और अधिक कठिन है, उपयुक्त अधिकारियों के लिए उन दो वैकल्पिक पाठ्यक्रमों में से एक या दूसरे का पालन करने के लिए कोई दिशानिर्देश निर्धारित किए बिना, यह क़ानून को संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल नहीं बनाता है। इसलिए पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 33 संविधान के अनुच्छेद 14 से परे नहीं है। (Para 1).

माननीय न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन द्वारा सितंबर, 1971 को श्री हरीश चंद के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए पूर्ण पीठ को भेजा गया मामला। माननीय मुख्य न्यायाधीश आर. एस. नरूला, माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रेम चंद जैन और माननीय न्यायमूर्ति एम. आर. शर्मा की पूर्ण पीठ ने अंततः 6 अगस्त, 1974 को मामले का फैसला सुनाया।

शाम रतन नेवाई, हरियाणा राज्य आदि। (नरूला, C.J.) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका यह प्रार्थना करते हुए कि दिनांक 6 मार्च, 1969 और 13 अगस्त, 1970 (अनुलग्नक 'जी' और 'एच') के आक्षेपित आदेश को निरस्त करते हुए सर्टिओरारी, मैंडमस या किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए और आगे यह प्रार्थना करते हुए कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादियों को भूमि राजस्व के बकाया के रूप में ऋण की राशि का भुगतान करने से रोका जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से जे. एस. शाहपुरी, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों की ओर से हरियाणा के अतिरिक्त महाधिवक्ता सी. डी. दीवान और हरियाणा के सहायक महाधिवक्ता एच. एन. मेहतानी उपस्थित थे।

फैसला

न्यायालय का निर्णय दिया गया थाः-R. S. NARULA, C.J. –

1) पंजाब राज्य उद्योग सहायता अधिनियम, 1935 की धारा 35 के अधिकारों पर इस याचिका में मेरे विद्वान भाई पी. सी. जैन, जे. के समक्ष इस आधार पर सवाल उठाया गया था कि उक्त प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल है क्योंकि यह वसूली को प्रभावी बनाने के लिए दो प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है, जिनमें से एक दूसरे की तुलना में कठोर और अधिक कठिन है, उन दो वैकल्पिक पाठ्यक्रमों में से एक या दूसरे का पालन करने के लिए उपयुक्त अधिकारियों के लिए कोई दिशानिर्देश निर्धारित किए बिना। हरीश चंद बनाम अमृतसर के कलेक्टर और एक अन्य मामले में इस अदालत की पूर्ण पीठ ने इस पूर्व तर्क को पहले ही खारिज कर दिया था। (1). तथापि, याचिकाकर्ता के वकील ने विद्वत न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया कि हरीश चंद के मामले (1) (उपर्युक्त) में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अब उत्तरी भारत कैटरर्स (प्राइवेट) लिमिटेड और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और एक अन्य (2) में उच्चतम न्यायालय के उनके अधिपत्यों की घोषणा को ध्यान में रखते हुए आधार नहीं रखता है, जिसमें पंजाब सार्वजनिक परिसर और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम (1959 का 31) की धारा 5 को उसी आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भेदभावपूर्ण और उल्लंघनकारी माना गया था। चूंकि एकल न्यायाधीश को इस न्यायालय के पहले पूर्ण पीठ के फैसले के मद्देनजर उस प्रश्न पर आगे की दलीलें सुनना उचित नहीं लगा, इसलिए मामले को पूर्ण पीठ को भेज दिया गया। इस तरह यह मामला आज हमारे सामने रखा गया है।

2) (2) प्रारंभ में, हरियाणा राज्य के विद्वत अपर महाधिवक्ता, श्री सी. डी. दीवान ने मगनलाल छगनलाल (निजी) लिमिटेड बनाम बृहन्मुंबई नगर निगम और अन्य (और संबंधित मामलों) (3) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को हमारे संज्ञान में लाया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपत्यों को निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः -

"इसलिए, यह तर्क कि केवल दो प्रक्रियाओं की उपलब्धता उनमें से एक विशेष प्रक्रिया को दूषित कर देगी, कारण या प्राधिकरण द्वारा समर्थित नहीं है।
उत्तरी भारत के कैटरर्स मामले (2) (उपर्युक्त) से निपटने के लिए विशेष रूप से उनके लॉर्डशिप्स ने कहाः-"इसलिए, हम खुद को उत्तरी भारत के कैटरर्स मामले में बहुमत से सहमत होने में असमर्थ पाते हैं (2)" तय किए गए मामलों के गुणागुण पर, विभिन्न कानूनों के कुछ प्रावधानों के बारे में तर्क भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार से बाहर होने के कारण केवल दो प्रक्रियाओं के कारण प्रदान किया गया था, जिसमें से एक दो वैकल्पिक प्रक्रियाओं में से एक या दूसरे के चयन के लिए कोई दिशानिर्देश निर्धारित किए बिना दूसरी से अधिक कठोर थी, को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था।

3) इन परिस्थितियों में, उत्तर भारत कैटरर्स मामले (2) में उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में अवधारित विधि, हरीश चंद के मामले (1) में इस न्यायालय के पूर्व पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय का अनुसरण करने के लिए विद्वत एकल न्यायाधीश के मार्ग में क्षेत्र और एकमात्र बाधा नहीं प्रतीत होती है। इसलिये हमारा यह मत है कि उत्तर भारत कैटरर्स मामले (2) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय इन परिस्थितियों में इस न्यायालय के पूर्ववर्ती पूर्ण न्यायपीठ के निर्णय की शुद्धता को प्रभावित नहीं करता है जो अन्यथा हम पर बाध्यकारी है।

चूँकि इस मामले में विद्वत एकल न्यायाधीश के समक्ष किसी अन्य बिंदु पर तर्क नहीं दिया गया था और अब भी किसी को भी हमारे समक्ष प्रचार करने की मांग नहीं की गई है, इसलिए यह याचिका विफल होनी चाहिए और तदनुसार खारिज कर दी जाती है, हालांकि लागत के रूप में किसी भी आदेश के बिना।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कार्तिक शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

नूह, हरियाणा